पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (खं.पी.) सं- 2016 का 10

थाना कांड सं-29, वर्ष-2013 थाना-सिकरहट्टा जिला-भोजपुर थाना से उत्पन्न मामला

==========

फुलचंद्र पासवान @दारा स्वर्गीय केदार पासवान के पुत्र, निवासी, गाँव-एस. क्राहाता, थाना-सिक्राहाता, जिला-भोजपुर

.....अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रतिवादी

==========

उपस्थिति

अपीलार्थी/ के लिए : सुश्री प्रिया, न्यायमित्र

प्रतिवादीओं के लिए : श्री अजय मिश्रा, एपीपी

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – दोषसिद्धि के खिलाफ अपील - धारा 374(2)

*यदि पीड़ित गवाह "स्टर्लिंग गवाह" है, तो केवल उसके बयान के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है – कोई अतिरिक्त पुष्टि आवश्यक नहीं (संदर्भित:- राय संदीप बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2012) 8 एससीसी 21)। चिकित्सा साक्ष्य भी पीड़िता के मामले की पुष्टि करता है। पीड़िता 8 वर्षीय लड़की है – अपीलकर्ता पर झूठा आरोप लगाने का कोई कारण नहीं। अभियुक्त द्वारा झूठे आरोप का कोई बचाव नहीं उठाया गया – न तो गवाहों की जिरह के दौरान कोई सुझाव दिया गया, न ही अभियुक्त द्वारा धारा 313 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान में कोई स्पष्टीकरण दिया गया – जांच अधिकारी का बयान पीड़िता के दावे का समर्थन करता है – पूरी तरह से प्रमाणित और समर्थित – निचली अदालत ने कोई त्रुटि नहीं की है – अपील खारिज। (**पैराग्राफ-23 से 30**)*

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा

मौखिक निर्णय

(निर्णयः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

03-04-2024

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'आ.दं.सं.' के रूप में संदर्भित) की धारा-374 (2) के तहत दायर की गई है, जिसमें दोषसिद्धि के फैसले को चुनौती दी गई है। दिनांक 12.01.2015 और सजा का आदेश दिनांक 14.01.2015 जे. पी. मिश्रा द्वारा पारित किया गया, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो, भोजपुर, आरा में, पॉक्सो मामला संख्या 6/2023 के संबंध में, (2023 के सिकराहाटा थाना मामला संख्या 29 से उत्पन्न) द्वारा जिसे अपीलार्थी/दोषी को आई. पी. सी. की धारा-376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा-4 और 6 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और पॉक्सो अधिनियम की धारा-6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

2. शुरुआत में, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि श्री विद्वान वकील प्रभात कुमार सिंह अब तक अपीलार्थी की ओर से पेश हो रहे थे। हालाँकि, जब मामले को 01.04.2024 पर सुनवाई के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्होंने

पहले ही अपीलार्थी को कोई आपत्ति नहीं दी थी और उन्होंने कागजात वापस कर दिए हैं। इसलिए, वह अब इस मामले में पेश नहीं हो रहे हैं। अपील वर्ष 2016 की है और अभिलेख से यह पता चलता है कि अपीलार्थी पिछले 11 वर्षों से हिरासत में है। इसलिए, हमने इस मामले में अदालत की सहायता करने के लिए विद्वान वकील सुश्री प्रिया से अनुरोध किया था और उनकी सहमति से, उन्हें न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया जाता है। उनके अनुरोध पर, मामले को 02.04.2024 पर स्थगित कर दिया गया। एक बार फिर न्यायमित्र ने खुद को तैयार करने के लिए समय का अनुरोध किया और मामले को फिर से 03.04.2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

3. अपीलार्थी की ओर से न्यायमित्र सुश्री प्रिया और प्रत्यर्थी राज्य की ओर से श्री अजय मिश्रा ने अ.लो.अ. सीखा।

4. वर्तमान अपील दायर करने के लिए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः

“19.05.2013 की रात को, 08:00 बजे शाम को, सूचना देने वाले की बेटी, जिसकी उम्र लगभग 8 साल थी, शादी समारोह में खाना खाकर पड़ोस में सिनेमा देखने गई थी। 20.05.2013 पर, 03:00 पूर्वाहन, वह घर में रोते हुए आई और बताया कि सिनेमा देखने के दौरान वह सो गई जब उसी गाँव के रहने वाले लगभग 28 साल के केदार पासवान पुत्र फुलचंद्र पासवान उर्फ दारा उग्राम हकीक मियां के घर के पीछे कोली में ले गए और जबरन उसका मुंह बंद कर दिया और उसकी शील भंग कर दी। जब मुखबिर ने उसकी बेटी के अंडरवियर की जांच की, तो वह फटा हुआ था और खून से सना हुआ था और उसके निजी हिस्से से अभी भी खून बह रहा था।

5. प्राथमिक प्रतिवेदन रिपोर्ट दाखिल करने के बाद, जांच एजेंसी ने जांच की और जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और संबंधित दस्तावेज एकत्र किए और उसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। चूंकि मामला

विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था।

6. ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों से पूछताछ की।

7. विद्वान *न्यायमित्र* प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी को प्रश्नगत घटना में गलत तरीके से फंसाया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि केवल पीड़ित का बयान है, जिसकी आयु लगभग 8 वर्ष है, जिसके आधार पर विद्वत विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश दर्ज किया है। पीड़ित लड़की द्वारा लगाए गए आरोप के समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि जांच अधिकारी ने घटना स्थल से रक्त एकत्र किया था और पीड़ित लड़की के खून से सने कपड़ों को जब्त कर लिया गया था और आवश्यक विश्लेषण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेज दिया गया था, लेकिन एफ. एस. एल. रिपोर्ट को विद्वत ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चिकित्सा साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन नहीं करते हैं। इसलिए, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, जिसके बावजूद निचली अदालत ने विवादित निर्णय और आदेश पारित किया है।

8. विद्वान *न्यायमित्र* ने अंत में आग्रह किया कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए और इस प्रकार विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश के विवादित फैसले को रद्द कर दिया जाए और खारिज कर दिया जाए।

9. दूसरी ओर, विद्वान अ.लो.अ. ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।यह मुख्य रूप से तर्क दिया गया है कि वर्तमान नैतिक पतन का एक स्पष्ट मामला है।अपीलार्थी ने न तो किसी बचाव पक्ष के गवाह से पूछताछ की है और न ही अपनी

बेगुनाही साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश किया है। अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाने का कोई मकसद नहीं बताया गया है। पीड़ित धारा-161 और 164 के तहत दर्ज अपने बयानों में सुसंगत है। इस प्रकार, जब अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है, तो विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और सजा के आदेश का विवादित निर्णय पारित करते समय कोई त्रुटियां नहीं की गई है।इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रचार की गई दलीलों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का भी अध्ययन किया है और प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य का भी अध्ययन किया है।

11. इस स्तर पर, हम विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य की सराहना करना चाहेंगे।

12. अभि.सं. 1, अल्गू साह ने अभियोजन-मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें 'शत्रुतापूर्ण' घोषित किया गया है।

13. अभि.सं. 2, परशुराम राजभर, जब्त गामची का जब्ती-सूची गवाह है। उन्होंने कथित घटना पर कोई प्रकाश नहीं डाला है।

14. अभि.सं. 3 तुन्नी देवी पीड़ित लड़की की माँ और वर्तमान मामले की मुखबिर हैं। उसने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि एक साल पहले 8:00 बजे लगभग 9 वर्ष की आयु की उनकी बेटी शादी देखने गई, 3:00 बजे पूर्वाहन वह रोते हुए घर आई। जब उनसे रोने का कारण पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि फुलचंद्र ने उनके साथ गलत किया था। उसके निजी अंग फटे और क्षतिग्रस्त हो गए। उसने दारोगाजी को पूरी घटना

सुनाई। दारोगाजी ने उसे नोट किया और उसके समक्ष पढ़ा। दर्ज किए गए बयान से संतुष्ट होकर, उन्होंने उसी पर अपने अंगूठे का निशान लगाया। उनकी बेटी की भी चिकित्सकीय जांच की गई। उनकी बेटी का बयान भी अदालत में दर्ज किया गया था। पुलिस ने फिर से उसका बयान लिया था। उसने अपनी बेटी के खून के धब्बों (सलवार) को भी सौंप दिया था। उसने अदालत में मौजूद आरोपी की पहचान कर ली है।

14.1 अपनी जिरह में उसने कहा है कि शादी समारोह उसके पड़ोसी सहदेव के घर पर आयोजित किया गया था। उनका घर उनके घर से 4-5 घरों के बाद स्थित है। उनकी बेटी वहाँ अकेले सिनेमा देखने गई थी। जब तक वह सोने गई, तब तक उसकी बेटी वापस नहीं आई थी। वह 8:00 अपराह्न बजे उसे खोजने गई थी, जब विवाह जुलूस दरवाजे पर था और, क्योंकि उसकी बेटी पुरुष सदस्यों में थी, वह वहाँ नहीं गई। उसने किसी और से अपनी बेटी की तलाश करने का अनुरोध नहीं किया था। अगले दिन वह शुरुआती घंटों में सीकरहाटा पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुई थी जो लगभग 1 मील (कोस) है। केवल केवल उनके साथ थे। पुलिस स्टेशन से वह पीरो अस्पताल और वहाँ से सदर अस्पताल। पीरो अस्पताल के डॉक्टर ने उसकी बेटी का इलाज किया और उसे आगे के इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। उनकी बेटी की चिकित्सकीय जांच की गई। उनकी बेटी का डेढ़ महीने तक सदर अस्पताल, आरा में इलाज चला। उनकी बेटी के घावों को सिलवाया गया था। उसने पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के निचले कपड़े सौंप दिए थे। उसने यह भी कहा है कि फुलचंद्र ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि आरोपी फुलचंद्र ने उनकी बेटी पर कथित अपराध नहीं किया था।

15. अभि.सं. 4 पीड़ित लड़की है। उसने अपने जाँच प्रमुख में कहा है कि यह घटना एक साल पहले हुई थी। वह रात में ग्राम में चल रहे सिनेमा देखने गई थी और

फिल्म देखते हुए सो गई थी। दारा पासवान आया और उसे बताया कि उसकी माँ उसकी तलाश कर रही है। उसके दो नाम हैं। हालाँकि, वह उसका दूसरा नाम नहीं जानती है। वह उसे पास के कोली में ले गया और अपराध को अंजाम दिया। वह उसके शरीर पर लेटा और उसके गुप्तांगों को फाड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसके गुप्तांगों से खून बहने लगा। गवाह ने अपने गुप्त भाग की ओर इशारा करते हुए कहा कि यहाँ से खून बहने लगा था। जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी उसे अकेला छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद वह बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो वह धीरे-धीरे दीवार की मदद से खड़ी हो गई, रोते हुए घर गई और अपनी मां को घटना के बारे में बताया। उसकी मां उसे थाने ले गई और पुलिस को घटना की सूचना दी। उसकी चिकित्सकीय जांच की गई और इलाज भी किया गया। उसका बयान विद्वान दंडाधिकारी के सामने भी दर्ज किया गया था जिस पर उसने अपने अंगूठे का निशान लगाया था।

15.1 अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि शो एक तंबू (समियाना) में चल रहा था। जिस स्थान पर वह बैठी थीं, उसके पास कई लोग बैठे थे। फिल्म देखते हुए वह सो गई। जब वह जागी तो उसने खुद को कोली में पाया। वह जमीन पर लेटी हुई थी। जमीन पर काफी खून फैला हुआ था। यहां तक कि उसके कपड़े भी खून से सने थे। जब तक वह घर नहीं पहुंची तब तक खून बह रहा था, लेकिन जब तक वह पुलिस स्टेशन गई तब तक खून बहना बंद हो गया था। वह पुलिस स्टेशन से अस्पताल गई थी। वह यह नहीं बता सकती कि वह अस्पताल से कब लौटी। दारोगाजी ने उसके खून से सने कपड़े ले लिए थे। उसने पुलिस स्टेशन में बताने के बाद ही अदालत में घटना के बारे में बताया था। अदालत द्वारा समय अंतराल के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने मौन बनाए रखा। उसने कहा है कि जब वह अदालत में आई थी, तो खून बह रहा था।

16. अभि.सं. 5 नमिता सिंह हैं। उसने कहा है कि 22.05.2013 पर, वह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के रूप में तैनात थी और उसने आरा में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भोजपुर के निर्देश पर लगभग 8 साल की पीड़ित लड़की, पुत्री-जोखम राजबंशी, निवासी ग्राम और थाना सिकरहाटा, जिला-भोजपुर का बयान दर्ज किया था। उसने अपनी भाषा में आ.दं.सं धारा 164 के अंतर्गत करोड़ में पीड़िता का बयान दर्ज किया। पीड़ित लड़की का बयान उसकी कलम और हस्ताक्षर में है। उसी को एक्सट चिह्नित किया गया है। 2.बयान दर्ज कराने के समय पीड़िता की मां उसके साथ थी।

17. अभि.सं. 6 डॉ. पुष्पा हैं जिन्होंने पीड़ित लड़की की चिकित्सकीय जांच की है।उसने निम्नलिखित चोटें पाई हैंः

" योनि परीक्षण के अनुसार, हाइमेन अक्षत था। वहाँ पूर्ण पेरेनियल आँसू था।

विजिनल स्वाब लिया गया और सूक्ष्म जांच के लिए भेजा गया। सविता कुमारी द्वारा पहने गए स्वाब और कपड़ों को पी.एम.ची.एस. पटना भेजने के लिए पुलिस को सौंप दिया गया।

पीड़ित के किसी अन्य हिस्से पर चोट का कोई अन्य निशान नहीं मिला। योनि और स्मीयर परीक्षा से पता चलता है कि कोई शुक्राणु मृत या जीवित नहीं है। बहुत सारे लाल रक्त कोशिका पाए गए।

एक्स-रे श्रोणि से पता चलता है कि इलियाक एपोपिस दिखाई नहीं दिया। कूल्हे के जोड़ के आसपास एपिप्लिसिस फ्यूज नहीं हुआ है।

एक्स-रे कोहनी से पता चलता है कि एपिफिसिस प्रकट नहीं हुआ है।

एक्स-रे रिस्ट एपिफिसिस का संलयन नहीं हुआ। तो एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार उसकी उम्र शायद दस साल से कम है। यह मेडिकल रिपोर्ट मेरे लिखित और हस्ताक्षर में है। उसी को एक्सट 3 चिह्नित किया गया है।

18. इस स्तर पर, यह स्पष्ट करना प्रासंगिक है कि हालांकि अभि.सं. 6 के बयान में, नीचे उल्लिखित वाक्य है "हाइमेन बरकरार था।", हालाँकि, अभि.सं. 6 द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र में, जो उनकी अपनी कलम और हस्ताक्षर में है, उन्होंने लिखा है "हाइमेन बरकरार नहीं है।".

19. अभि.सं. 7 पूनम कुमारी जाँच अधिकारी हैं जिन्हें 20.05.2013 पर महिला पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया था। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि पीड़ित द्वारा पहने गए कपड़े खून और वीर्य से रंगे हुए थे। उन्होंने जब्त सूची तैयार की जिसे प्रदर्शनी-4 के रूप में चिह्नित किया गया है। उसने गवाहों के सामने आरोपी द्वारा पहने गए कपड़ों और जींस पैंट की भी तलाशी ली और उसके दोनों जींस पैंट के निचले पैरों पर खून के धब्बे पाए। इसके अलावा, यह कहा गया है कि आरोपी ने सुनसान गली में पीड़ित लड़की के साथ जबरन बलात्कार किया था। यह भी कहा गया है कि परशुराम राजवार ने जब्ती-सूची पर अपने बाएं अंगूठे का निशान दिया था। जब्ती सूची को प्रदर्शनी-4/बी के रूप में चिह्नित किया गया था। इसके बाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आ.दं.सं. की धारा 164 के तहत पीड़ित का बयान दर्ज करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। एफ. एस. एल. दल द्वारा घटना स्थल से मिट्टी जब्त कर ली गई थी जिसे प्रदर्शित किया गया था। उसने जेल अधीक्षक से आरोपी को उसके खून की जांच कराने के लिए मनाने का अनुरोध किया।

19.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि काले *सलवार* से एक लाल रंग का पदार्थ जब्त किया गया था। आरोपी के नीले रंग के पैंट के निचले हिस्से में खून जैसा

पदार्थ था जिसे जब्त कर लिया गया था। अभियुक्त के घर से एक गंदा सफेद रंग का तौलिया *(गमछी)* जब्त किया गया था जिसमें खून और वीर्य जैसे दाग पाए गए थे। जब्त की गई सभी वस्तुओं को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, पटना भेजा गया। पीड़ित द्वारा पहने गए कपड़े भी तुन्नी देवी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे जिन्हें जब्त कर लिया गया था और एक जब्ती सूची तैयार की गई थी और एफ. एस. एल. पटना को भेजी गई थी।

20. अभि.सं. 8 बीरेंद्र साह एक अधिवक्ता क्लर्क हैं। वह प्राथमिक प्रतिवेदन रिपोर्ट का गवाह है। उसने केवल सीकरहाटा पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एस. एच. ओ. की कलम और हस्ताक्षर में लिखित जानकारी की पहचान की है।

21. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रचार की गई दलीलों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना की है। हमने अभिलेख पर रखी गई सामग्री का भी अध्ययन किया है।

22. रिकॉर्ड से पता चलता है कि पीड़ित की मां का *फरदबेयान* तुरंत रिकॉर्ड किया गया था जब पीड़िता रोते हुए घर आई और बताया कि सिनेमा देखने के दौरान, वह सो गई जब आरोपी फुलचंद्र पासवान उसे हाकिक मियां और जबरन उसका मुँह बंद कर दिया और उसकी शील भंग कर दी। इस प्रकार, पीड़ित की मां ने तुरंत प्राथमिक प्रतिवेदन रिपोर्ट दर्ज कराया। इससे आगे पता चलेगा कि सूचना देने वाले, पीड़ित की मां ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। यहां तक कि पीड़ित लड़की का बयान, जिसकी उम्र लगभग 8 साल है, पुलिस द्वारा आ.दं.सं. की धारा-161 के तहत दर्ज किया गया था। पीड़ित को तुरंत चिकित्सा जांच के लिए भेज दिया गया था। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट द्वारा धारा-164 आ.दं.सं. के तहत पीड़ित का बयान भी दर्ज किया गया था। जिस मजिस्ट्रेट ने पीड़िता का बयान दर्ज किया था, उसने भी निचली अदालत के समक्ष

अपना बयान दिया है। पीड़िता ने अदालत के समक्ष अपना बयान भी दिया है। पीड़ित ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है।

23. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि **राय संदीप बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)** का मामला **(2012) 8 एस. सी. सी. 21,** माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा-22 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

"22. हमारी सुविचारित राय में, "उत्कृष्ट गवाह" बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए जिसका संस्करण, इसलिए, अकाट्य होना चाहिए। ऐसे गवाह के कथन पर विचार करते हुए अदालत को इसे बिना किसी हिचकिचाहट के इसके विश्वसनीय मूल्य के लिए स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे गवाह की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, गवाह की स्थिति महत्वहीन होगी और जो प्रासंगिक होगा वह ऐसे गवाह द्वारा दिए गए बयान की सच्चाई। जो अधिक प्रासंगिक होगा वह प्रारंभिक बिंदु से अंत तक बयान की स्थिरता होगी, अर्थात् उस समय जब गवाह प्रारंभिक बयान देता है और अंततः अदालत के समक्ष। यह प्राकृतिक और आरोपी के अभियोजन पक्ष के मामलें के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे गवाह के कथन में कोई छल-कपट नहीं होना चाहिए। गवाह को किसी भी अवधि के क्रॉससेक्सैमिनेशन का सामना करने की स्थिति में होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्तियों के साथ-साथ इसके अनुक्रम के बारे में किसी भी संदेह के लिए जगह नहीं देनी चाहिए। इस तरह के कथन का अन्य सहायक सामग्री के प्रत्येक के साथ सह-संबंध होना चाहिए जैसे कि बरामदगी, उपयोग किए गए हथियार, किए गए अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय/कथित कथन को लगातार प्रत्येक अन्य गवाह के कथन से सही रुप से मेल खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू परीक्षण के समान होना चाहिए जहां आरोपी

को उसके विरुद्ध अभिकथित अपराध का अपराधी ठहराने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई संपर्क नहीं टूटना चाहिए। केवल तभी जब ऐसे गवाह का संस्करण उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ लागू किए जाने वाले अन्य सभी समान परीक्षणों के योग्य हो जाता है, तो यह माना जा सकता है कि ऐसे गवाह को "उत्कृष्ट गवाह" के रूप में बुलाया जा सकता है जिसका संस्करण अदालत द्वारा बिना किसी पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक सटीक रूप से कहें तो, अपराध के मुख्य बिन्दु पर कथित गवाह का कथन अखंड रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी प्रस्तुत सहायक सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तओं को सामग्री विवरणों में कथित कथन से मेल खाना चाहिए, ताकि अपराध का विचारण करने वाले अदालत को अपराधी को दोषसिद्घ करने के लिए अन्य सहायक सामग्री को छानने के लिए मुख्य कथन पर भरोसा करने में सक्षम बनाया जा सके।

24. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए उपरोक्त अवलोकन से, यह कहा जा सकता है कि यदि गवाह, जो पीड़ित है, को एक उत्कृष्ट गवाह माना जाता है, तो केवल उसी पर भरोसा किया जा सकता है, दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है और आगे किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।

25. हमने धारा-164 आ.दं.सं. के तहत दर्ज पीड़ित के बयान और उसी को दर्ज करने वाले विद्वान दंडाधिकारी द्वारा दिए गए बयान को देखा है और हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में अभि.सं. 4, पीड़ित को एक उत्कृष्ट गवाह कहा जा सकता है।

26. यहां तक कि डॉक्टर द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र में भी यह देखा गया है कि पीड़ित लड़की का हाइमेन बरकरार नहीं था। इस प्रकार, हमारा विचार

है कि चिकित्सा साक्ष्य भी पीड़ित द्वारा दिए गए संस्करण का समर्थन करते हैं। इस प्रकार, चिकित्सा साक्ष्य पीड़ित के मामले की पुष्टि करते हैं।

27. इस स्तर पर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीड़ित, जिसकी आयु लगभग 8 वर्ष है, और उसकी माँ, यानी सूचना देने वाले के पास अपीलार्थी को इसमें गलत तरीके से फंसाने का कोई कारण नहीं है। अभियुक्त ने यह भी कोई बचाव नहीं किया है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है।गवाहों से जिरह के दौरान कोई सुझाव नहीं दिया गया था और न ही धारा-313 आ.दं.सं. के तहत दर्ज अभियुक्त के बयान में कोई स्पष्टीकरण है।

28. जाँच अधिकारी के बयान से यह भी पता चलता है कि उसने घटना स्थल से खून एकत्र किया था और घटना स्थल से जब्त किए गए खून को पीड़ित के खून से सने कपड़ों के साथ आवश्यक विश्लेषण के लिए एफ. एस. एल., पटना भेजा था। इस प्रकार, जांच अधिकारी द्वारा दिए गए बयान से भी, पीड़ित लड़की द्वारा दिए गए बयान को पूरी तरह से प्रमाणित और समर्थित पाया जाता है।

29. हमने विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए तर्क को भी देखा है और हमारा विचार है कि निचली अदालत ने कोई त्रुटियां नहीं की है। इसलिए, वर्तमान अपील में निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

30. तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज कर दी जाती है।

31. अपील को छोड़ने से पहले, हम अपने **सुश्री प्रिया** द्वारा प्रदान की गई सक्षम सहायता के लिए सराहना, उन्होंने *न्यायमित्र* सीखा।

32. पटना उच्च न्यायालय की कानूनी सेवा समिति को इसके द्वारा **3,000 (तीन हजार रुपये)** का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। सुश्री प्रिया को, न्यायमित्र के रूप में सीखा उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए समेकित शुल्क।

(विपुल एम. पंचोली न्यायमूर्ति)

(सुनील दत्ता मिश्रा,न्यायमूर्ति)

के.सी.झा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।